+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(19 February 2025)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- रूस-अमेरिका अपने संबंधों को सुधारने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने पर सहमत
- भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर बढ़ाया
- बैंकों में जमाओं पर बीमा कवर क्या है, और इसे बढ़ाने से लोगों को किस प्रकार मदद मिलेगी?

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

रूस-अमेरिका अपने संबंधों को सुधारने और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में काम करने पर सहमत:

चर्चा में क्यों है?

- एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक बदलाव के रूप में, शीर्ष अमेरिकी और रूसी राजनयिकों ने यूक्रेन में लगभग तीन साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने और टूटे हुए राजनयिक संबंधों को सुधारने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 18 फरवरी को रियाद में मुलाकात की।

- रूस के 2022 के आक्रमण के बाद से सबसे व्यापक अमेरिका-रूस कूटनीतिक जुड़ाव के रूप में इस बैठक ने, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के तहत अमेरिकी विदेश नीति में अप्रत्याशित मोड़ का संकेत दिया है। इस बैठक में दोनों पक्ष अपने संबंधों में "गड़बड़ियों" को दूर करने, यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने और अपने कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू करने पर सहमत हुए।

- उल्लेखनीय है कि इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ-साथ दोनों देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने भाग लिया। साथ ही बैठक में रूस के प्रति पिछले अमेरिकी प्रशासन के सख्त रवैये से अलग रुख देखने को मिला।

रियाद बैठक में तीन प्रमुख कूटनीतिक लक्ष्य तय:

- अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि दोनों पक्ष मोटे तौर पर तीन कूटनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए: वाशिंगटन और मॉस्को में अपने-अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या बहाल करना, यूक्रेन शांति वार्ता का समर्थन करने के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाना और करीबी संबंधों और आर्थिक सहयोग की तलाश करना।

अपने-अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या बहाल करना:

- दोनों देशों को हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक असफलताओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें दूतावास में कर्मचारियों की संख्या ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गई है, जिसके बाद राजनयिक निष्कासन की एक श्रृंखला शुरू हुई।

- अमेरिका और रूस ने राजदूतों और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों की पुनर्नियुक्ति को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमति जताई, जो उनके तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने की दिशा में पहला बड़ा कदम है।

यूक्रेन शांति वार्ता के लिए एक उच्च स्तरीय टीम बनाना:

- यूक्रेन के लिए शांति वार्ता का समर्थन करने के लिए एक उच्च-स्तरीय कार्य समूह का गठन करना शामिल है।
- हालांकि इन वार्ताओं का विवरण अस्पष्ट है, रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने स्वीकार किया कि अमेरिका यूक्रेन पर "अपनी स्थिति को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर रहा है", यह दर्शाता है कि रूस को उम्मीद है कि अमेरिका क्षेत्रीय नियंत्रण और सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर अधिक लचीला होगा।

करीबी संबंधों और आर्थिक सहयोग की तलाश करना:

- दोनों पक्षों ने संयुक्त ऊर्जा उपक्रमों की संभावना सहित आर्थिक सहयोग को पुनर्जीवित करने में रुचि व्यक्त की।
- रूस के अनुसार ऊर्जा साझेदारी, विशेष रूप से आर्कटिक में, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

रूस-अमेरिका संबंधों में सुधार की पहल:

- हाल के वर्षों में रूस और अमेरिका के बीच संबंध दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं - यह दरार तब से बढ़ रही है जब से रूस ने 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया को अपने कब्जे में लिया था और रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के बाद और भी बदतर हो गई। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से अमेरिका ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के प्रयास में उस पर कई प्रतिबंध लगाए। और वाशिंगटन और मॉस्को में दूतावास को बड़ी संख्या में राजनयिकों के निष्कासन के साथ-साथ अन्य प्रतिबंधों से भी कड़ी चोट लगी है।
- अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने से "आम हितों के मुद्दों पर और स्पष्ट रूप से, आर्थिक रूप से रूस के साथ साझेदारी करने के लिए मौजूद अविश्वसनीय अवसरों के लिए" "दरवाजे खुल सकते हैं" जो उम्मीद है कि दुनिया के लिए अच्छे होंगे और लंबी अवधि में हमारे संबंधों को भी बेहतर बनाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि यह बैठक रूस के 24 फरवरी, 2022 के आक्रमण के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे व्यापक संपर्क को चिह्नित करती है। क्योंकि रूसी विदेश

मंत्री लावरोव और तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लगभग दो साल पहले भारत में G20 बैठक के दौरान संक्षिप्त बातचीत की थी, लेकिन तनाव उच्च स्तर पर बना रहा।

अमेरिका सहयोगियों की चिंताओं को दरकिनार कर रहा है:

- यूक्रेन युद्ध पर हाल ही में अमेरिकी कूटनीतिक दृष्टिकोण में बदलाव ने यूक्रेन और प्रमुख सहयोगियों को इस बात के लिए विचार ने पर मजबूर कर दिया है कि वे इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अमेरिका और रूस किसी ऐसे समझौते पर आगे बढ़ सकते हैं जो उनके अनुकूल नहीं होगा।
- उल्लेखनीय है कि रियाद वार्ता में यूक्रेन की अनुपस्थिति ने यूक्रेन को परेशान कर दिया, और फ्रांस ने युद्ध पर चर्चा करने के लिए 17 फरवरी को यूरोपीय संघ के देशों और ब्रिटेन के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। क्योंकि इस तरह की वार्ता में यूक्रेन की भागीदारी जो बिडेन के तहत अमेरिकी नीति का आधार थी।
- वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेग ने पिछले हफ्ते कहा था कि यूक्रेन के लिए नाटो की सदस्यता अवास्तविक है और उन्होंने सुझाव दिया कि यूक्रेन को रूस से अपने सभी क्षेत्रों को वापस जीतने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

यूक्रेन युद्ध में शांति का आगे का रास्ता:

- उल्लेखनीय है कि रियाद में कूटनीतिक प्रगति के बावजूद, यूक्रेन युद्ध को लेकर व्यापक शांति समझौते तक पहुँचने में महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं।
- क्योंकि यूक्रेन में युद्ध कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, रूसी सेनाओं ने यूक्रेन में नागरिक बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले जारी रखे हुए हैं।
- इसके अलावा, यूक्रेन और प्रमुख यूरोपीय सहयोगी अभी भी वार्ता की मेज से अनुपस्थित हैं, इसलिए स्थायी शांति की संभावनाएं अनिश्चित बनी हुई है। जैसे-जैसे अमेरिका और रूस आगे की वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं, यह सवाल कि यूक्रेन सहित सभी पक्षों को कैसे शामिल किया जाए, किसी भी कूटनीतिक पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा।
- हालांकि रियाद वार्ता ने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेकिन आगे का रास्ता जटिलताओं से भरा हुआ है। अमेरिका और रूस दोनों को अब एक नाजुक कूटनीतिक संतुलन बनाना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि संबंधों को फिर से बनाने के उनके प्रयास यूक्रेन या व्यापक ट्रांसअटलांटिक गठबंधन की कीमत पर न हों।

भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर पर बढ़ाया:

परिचय:

- भारत और कतर ने 18 फरवरी को अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 30 अरब डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी ने व्यापार और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और इजरायल-हमास संघर्ष सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की।

- प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली पहुंचने पर व्यक्तिगत रूप से कतर के अमीर का स्वागत किया, जिससे भारत द्वारा द्विपक्षीय संबंधों को दिए गए महत्व का संकेत मिला।

भारत-क़तर रणनीतिक साझेदारी समझौता:

- भारत और कतर ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया, तथा भारत के प्रधानमंत्री और कतर के अमीर की उपस्थिति में भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी की स्थापना पर समझौते का आदान-प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि रणनीतिक साझेदारी समझौते से दोनों पक्षों को व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घनिष्ठ सहयोग की सुविधा मिलेगी।
- इस अवसर पर भारत और कतर ने व्यापार, ऊर्जा, निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान किया।
- उल्लेखनीय है कि भारत की वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के चार अन्य सदस्यों - संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान और कुवैत के साथ रणनीतिक साझेदारी है। GCC सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है, जिसकी स्थापना मई 1981 में सऊदी अरब के रियाद में हुई थी।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को बढ़वा देने पर बल:

- उल्लेखनीय है कि व्यापार और वाणिज्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का एक मजबूत स्तंभ रहा है तथा उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार में और अधिक वृद्धि एवं विविधीकरण की संभावना पर बल दिया।
- दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने और विविधतापूर्ण बनाने के लिए रणनीतियां तलाशने की आवश्यकता पर सहमति जताई और वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार से संबंधित बाजार पहुंच के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया। इस संबंध में, दोनों पक्ष द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में प्रवेश करने की संभावना तलाशने पर सहमत हुए।
- दोनों पक्षों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर लगभग 30 अरब डॉलर करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों पक्ष विभिन्न विधानों और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने और गहन बनाने पर सहमत हुए हैं।
- दोनों पक्षों ने दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के लिए राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- कतर नेशनल बैंक के बिक्री केन्द्रों में भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) की शुरुआत के बाद, कतर में UPI को राष्ट्रव्यापी स्तर पर शुरू करने की योजना है। दोनों पक्ष राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं।

द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने पर बल:

- दोनों पक्ष द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और बढ़ाने के लिए काम करेंगे, जिसमें ऊर्जा अवसंरचना में व्यापार और आपसी निवेश को बढ़ावा देना तथा ऊर्जा पर संयुक्त कार्यबल सहित दोनों पक्षों के संबंधित हितधारकों की नियमित बैठकें शामिल होंगी।
- उल्लेखनीय है कि कतर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का सबसे बड़ा प्रदाता है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 10.91 मिलियन मीट्रिक टन LNG और 4.92 मिलियन मीट्रिक टन LPG की आपूर्ति करेगा। साथ ही कतर एनर्जी और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड ने फरवरी 2024 में भारत को 2028 से शुरू होने वाले 20 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत में क़तर के निवेश को बढ़ने पर बल:

- कतर ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाने में भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और बुनियादी ढांचे,

प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, खाद्य सुरक्षा, रसद, आतिथ्य और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाने में रुचि व्यक्त की।

- इस संबंध में, कतर ने भारत में 10 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। कतर के सरकारी निवेश संस्था, कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में संभावित निवेश के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा, बंदरगाह, जहाज निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य पार्क, स्टार्टअप और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स जैसी नई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि कतर निवेश प्राधिकरण ने अब तक भारत में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1.5 अरब डॉलर का निवेश किया है।

लोगों के मध्य संबंधों को और बढ़ावा देने पर बल:

- दोनों पक्षों ने माना कि दोनों देशों के मध्य सदियों पुराने लोगों के बीच संबंध ऐतिहासिक भारत-कतर संबंधों के मूलभूत स्तंभ का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- कतर ने मेजबान देश की प्रगति और विकास के लिए कतर में भारतीय समुदाय द्वारा की गई भूमिका और योगदान के लिए गहरी सराहना व्यक्त की, और कहा कि कतर में भारतीय नागरिकों को उनके शांतिपूर्ण और मेहनती स्वभाव के लिए बहुत सम्मान दिया जाता है।

- भारतीय पक्ष ने कतर में इस बड़े और जीवंत भारतीय समुदाय (8 लाख से ज्यादा) के कल्याण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए कतर के नेतृत्व की गहरी सराहना की। साथ ही दोनों पक्षों ने जनशक्ति गतिशीलता और मानव संसाधन के क्षेत्र में दीर्घकालिक और ऐतिहासिक सहयोग की गहराई और महत्व पर जोर दिया।

आतंकवाद सहित आंतरिक सुरक्षा पर सहयोग:

- दोनों नेताओं ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की और द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से इस खतरे से निपटने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देश सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने और कानून प्रवर्तन, धन शोधन विरोधी, मादक पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध और अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों में सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए।
- दोनों नेताओं ने आतंकवाद, कट्टरपंथ और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए साइबरस्पेस के उपयोग की रोकथाम सहित साइबर सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा की।

दोनों देशों के मध्य सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- **स्वास्थ्य सहयोग:** दोनों पक्षों ने स्वास्थ्य सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक माना और कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य पर संयुक्त कार्य समूह के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। भारतीय पक्ष ने कतर को भारतीय दवा उत्पादों और चिकित्सा उपकरणों के निर्यात को बढ़ाने में रुचि व्यक्त की।
- **प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग:** दोनों पक्षों ने उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित प्रौद्योगिकी और नवाचार में गहन सहयोग को आगे बढ़ाने में रुचि व्यक्त की। उन्होंने ई-गवर्नेंस को आगे बढ़ाने और डिजिटल क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के अवसरों पर चर्चा की।
- **खाद्य सुरक्षा पर सहयोग:** दोनों पक्षों ने खाद्य सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं के संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और इस क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** दोनों पक्षों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी के आदान-प्रदान और दोनों देशों में सांस्कृतिक संस्थानों के बीच प्रभावी साझेदारी का समर्थन करके सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।

बैंकों में जमाओं पर बीमा कवर क्या है, और इसे बढ़ाने से लोगों को किस प्रकार मदद मिलेगी?

चर्चा में क्यों है?

- वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने 17 फरवरी को कहा कि भारत सरकार बैंक जमाओं के लिए बीमा कवर को 5 लाख रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाने पर विचार कर रही है। जमाओं के लिए बीमा कवर भारतीय रिजर्व बैंक के एक विशेष प्रभाग, 'निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (DICGC)' द्वारा प्रदान किया जाता है।

- उल्लेखनीय है कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक जैसे मामले में सरकार के आगे की कार्यवाही पर पूछे जाने पर, नागराजू ने कहा कि "(जमा) बीमा बढ़ाने" का प्रस्ताव "सक्रिय रूप से विचाराधीन" है, और "जैसे ही सरकार मंजूरी देगी, हम इसे अधिसूचित कर देंगे"।

न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक मामले में RBI ने क्या कार्रवाई की है?

- उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह RBI द्वारा मुंबई स्थित न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें पर्यवेक्षी चिंताओं और "खराब शासन मानकों" का हवाला देते हुए इसके निदेशक मंडल को 12 महीने के लिए बर्खास्त करना शामिल है। RBI ने बैंक को निर्देश दिया है कि वह कोई भी ऋण या अग्रिम न दे या उसका नवीनीकरण न करे; कोई निवेश न करे; उधार लेने और नई जमाराशि स्वीकार करने सहित कोई भी देनदारी न उठाए; या बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के कोई भी भुगतान न करे या न ही करने के लिए सहमत हो। ये प्रतिबंध 13 फरवरी के बाद लागू हुए और छह महीने तक लागू रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और पुणे और गुजरात के सूरत में 30 शाखाएं हैं। मार्च 2024 के अंत में, बैंक के पास 2,436 करोड़ रुपये का जमा आधार था और इसने 2023-24 में 22.78 करोड़ रुपये और 2022-23 में 30.74 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया था।

बैंक जमा राशियों का बीमा कैसे किया जाता है?

- रिज़र्व बैंक के विशेष प्रभाग, DICGC का उद्देश्य बैंक की विफलता की स्थिति में “छोटे जमाकर्ताओं” को उनके बचत खोने के जोखिम से बचाना है। इसके लिए प्रति

जमाकर्ता 5 लाख रुपये का बीमा कवर बीमित बैंक की सभी शाखाओं में जमाकर्ता द्वारा रखे गए सभी खातों (बचत, सावधि, चालू और आवर्ती जमाराशियों) के लिए है।

- DICGC भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों की शाखाओं, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों का बीमा करता है।
- हालाँकि, DICGC द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों का बीमा नहीं किया जाता है। साथ ही विदेशी, केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा जमाराशियों और अंतर-बैंक जमा राशियों के लिए बीमा प्रदान नहीं करता है।
- जमा बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान बीमित बैंक द्वारा किया जाता है। DICGC बैंक के जोखिम प्रोफाइल के आधार पर एक समान या विभेदित दर पर प्रीमियम एकत्र करता है।
- यदि बैंक परिसमापन में चला जाता है, तो DICGC परिसमापक से दावा सूची प्राप्त होने की तिथि से दो महीने के भीतर प्रत्येक जमाकर्ता की दावा राशि 5 लाख रुपये तक का भुगतान परिसमापक को करने के लिए उत्तरदायी है। परिसमापक को प्रत्येक बीमित जमाकर्ता को सही दावा राशि वितरित करनी होगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

जमा बीमा बढ़ाने से लोगों को किस प्रकार मदद मिलेगी?

- रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव ने पिछले साल कहा था कि 31 मार्च, 2024 तक पूरी तरह से सुरक्षित खाते कुल खातों का 97.8% थे, जो 80% के अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से अधिक है। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि आगे चलकर चुनौतियां आने की संभावना है, क्योंकि बढ़ती और औपचारिक होती अर्थव्यवस्था में प्राथमिक और द्वितीयक बैंक जमा दोनों में तेज वृद्धि देखने को मिल सकती है।
- ऐसे में बैंक जमाओं के बीमा कवर में वृद्धि न केवल न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक जैसे बैंक की विफलता के मामले में जमाकर्ताओं के हितों की अधिक हद तक रक्षा करेगी, बल्कि इससे बैंकिंग प्रणाली में उनका भरोसा और विश्वास भी मजबूत होगा।